political consensus on the passing of this Bill. On the advice of this Ministry Law Commission has now taken up a study for formulating requisite law for combating terrorism in the country.

नये राज्यों का सृजन

2725. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा हाल में कितने राज्यों का सृजन किया गया है और संविधान के अनुसार अनुमोदित किया गया है;

(ख) ऐसे राज्यों के नाम क्या-क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावित राज्यों की राजधानियों की भी पहचान कर ली गई है;

(घ) नए राज्य बनाने के लिए सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र को भी पृथक राज्य बनाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है; तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) सरकार ने हाल में किसी राज्य का पुर्नगठन नहीं किया है।

(घ) और (ङ) नए राज्यों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तथापि, सरकार राज्यों के किसी सामान्य पुनर्गठन पर कोई विचार नहीं कर रही है। इस समय, मौजूदा बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि वनांचल, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड/उत्तरांचल नए राज्यों का सृजन किया जा सके।

Assam-Arunachal Pradesh Boundary Dispute

2726. SHRI NABAM REBIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a long standing boundary dispute exists between Assam and Arunachal Pradesh;

(b) whether it is also a fact that the Assam Police and Forest Department are frequently encroaching upon Arunachal Land thereby subjecting innocent Arunachal people to inhuman torture and eviction;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps taken to resolve this long-standing vexed problem?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Arunachal Pradesh Government have complained about incidents of encroaching by the Assam Police and Assam Forest Department inside Arunachal Pradesh and eviction of Arunachal villagers.

Government of Assam have, however, informed that no encroachment in the territory of Arunachal Pradesh is being done by the Assam Police or Forest Department.

(d) Government has directed both the State Governments to maintain status quo and resolve the problem amicably. Bilateral negotiations at the level of Chief Ministers of both the State Government have taken place. A Joint Ministerial Committee has been constituted by the two State Governments to resolve the boundary dispute.

Government of Assam have informed that they have taken steps for revival and expeditious disposal of the title Suit No. 1/89 pending in the Hon'ble Supreme Court of India in connection with Assam-Arunachal Pradesh boundary dispute.

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थों में आत्मनिर्भरता

2727. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में पेट्रोलियम तथा उससे संबंधित पदार्थों की मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन के साथ साथ आयात का सहारा भी लेना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो गत 5 वर्षों के दौरान स्वदेशी उत्पादन तथा आयात के माध्यम से औसतन कितने प्रतिशत मांग पूरी की जाती रही है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में इस मांग को केवल स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से ही पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो इस संबंध में समयबद्ध लक्ष्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान देशी उत्पादन तथा आयातों द्वारा पूरी की गई मांग का प्रतिशत निम्नानुसार है;

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
पेट्रोलियम उत्पादों के देशी उत्पादन द्वारा पूरी की गई मांग का प्रतिशत	84	79	74	75	73
पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों द्वारा पूरी की गई मांग का प्रतिशत	16	21	26	[illegible]	27

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए, उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग, रिजर्वायर की स्थिति के बेहतर समझ, नए क्षेत्रों के विकास, मौजूदा क्षेत्रों के अतिरिक्त विकास तथा अपस्ट्रीम क्षेत्र में विदेशी तथा निजी पूंजी को आमंत्रित करते हुए, देश में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूदा रिफाइनरियों के विस्तार तथा संयुक्त क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में रिफाइनरियां लगाकर देश की शोधन क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है।

Sale of products of Reliance and Essar

2728. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS bé pleased to state:

(a) whether it is a fact that Indian Oil Corporation propose to set up a separate marketing company to sell products of private sector refineries of Reliance and Essar; and

(b) if so, what are the details of the deal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) and (b) the Indian Oil Corporation is negotiating arrangements with Reliance Petroleum Limited and Essar Oil Limited in regard to the marketing of controlled products of their refineries, in accordance with the approved guidelines and policies of the Government of India.

रसोई गैस संबंधी आर्थिक समझौता

2729. **प्रो॰ रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस पर आर्थिक सहायता को समाप्त करने संबंधी निर्णय ले लिया है अथवा लेने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसकी समयावधि क्या है, और

(ग) रसोई गैस पर आर्थिक सहायता को समाप्त किये जाने के बाद इसकी कीमतों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव से आम जनता को बचाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार ने नवम्बर, 1997 में यह निर्णय लिया था कि एल॰ पी॰ जी॰ पर राजसहायता चरणों से कम की जाएगी, ताकि वर्ष 2000-01 तक यह आयात समता